



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 24 फाल्गुन, शक संवत्, 1934

(दिनांक : 15 मार्च, 2013)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन

1. प्रश्न (दिखिए नत्यी "क")।
2. निधन के निदेश।
3. मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अन्वर्गत उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार जियमावली, 2012 को सदन के पट्टन पर रखेंगे।
4. प्रगुण सचिव विधान सभा उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्वर्गत महामहिम राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुर्वविचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को सदन के पट्टन पर रखेंगे।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-
 (1) उत्तराखण्ड विभिन्नों (2012-2013 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2012 का वारहवां अधिनियम बन गया।
 (2) विधिध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का पहला अधिनियम बन गया।

- (3) पं० दीवदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का दूसरा अधिनियम बन गया।
- (4) ग्राफिक एवा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का तीसरा अधिनियम बन गया।
- (5) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मध्यी विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 01 जनवरी 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का चौथा अधिनियम बन गया।
- (6) उत्तराखण्ड राज्य एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 जनवरी 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का पांचवां अधिनियम बन गया।
- (7) उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकरण विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 जनवरी 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का छठा अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेपण विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 जनवरी 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का सातवां अधिनियम बन गया।
- (9) उत्तराखण्ड मोटरवाहन कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 जनवरी 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का आठवां अधिनियम बन गया।
- (10) उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल उपयोग कर विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 जनवरी 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का नवां अधिनियम बन गया।

- (11) डी०आई०टी० विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का दसवां अधिनियम बन गया।
- (12) उल्लंघन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का चारहवां अधिनियम बन गया।
- (13) हिमालयन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का चारहवां अधिनियम बन गया।
- (14) आई०एम०एस० यूनिसन विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 फरवरी, 2013 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2013 का तेस्रहवां अधिनियम बन गया।

6. सदस्यों की शिरकतारी, विरोध व रिहाई की सूचबाब्द, यदि कोई हो।
- (मुद्रित प्रतियां बाद 7. में वितरित की जायेगी)
7. उपाध्यक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड तृतीय विधान सभा की याचिका समिति (2012-13) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
8. श्री ललित फर्खाण, सदस्य, विधान सभा, "जबपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट (मल्ला दाबपुर) के ग्राम पंचायत रातिरक्लेटी में हाईस्कूल का उच्चीकरण कराये जाने के संबंध में" श्रीमती दीपा देवी निवासी- ग्राम पंचायत कीमू एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्री ललित फर्खाण, सदस्य, विधान सभा, "जबपद बागेश्वर में विकास खण्ड कपकोट के गैरखेत-हरसीला तक 04 कि०मी० कपकोट-पोलिंग मोटर मार्ग का विस्तार कराये जाने के संबंध में" श्रीमती निर्मला देवी, निवासी- ग्राम पंचायत हरसीला एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री ललित फर्खाण, सदस्य, विधान सभा, "जबपद बागेश्वर की अनुसूचित वस्ती चबोला में राजकीय जूनियर हाईस्कूल व गांव को जोड़ने के लिए बूडाणाड़ नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के संबंध में" श्रीमती जावकी देवी, निवासी- ग्राम पंचायत चबोला एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री ललित फर्हाण, सदस्य, विधाव सभा, “जबपद बागेश्वर के शाम पंचायत बरगोली में प्राथमिक विद्यालय एवं गांव को जोड़ने के लिए चूड़ागाढ़ नदी पर अबुसूचित बक्सी बलोला में राजकीय जूनियर हाईस्कूल व गांव को जोड़ने के लिए चूड़ागाढ़ नदी पर स्टील गार्डर पुल बनाये जाने के संबंध में” श्रीमती द्रौपती देवी, विवासी- शाम पंचायत बरगोली एवं अन्य विवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
12. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हो।
13. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत मानवीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएँ, यदि कोई हों।
14. नंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
15. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विविध अधिकारियम विधिमाल्यकरण विधेयक, 2013 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
16. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विविध अधिकारियम विधिमाल्यकरण विधेयक, 2013 को पुरस्थापित करेंगे।
17. वित्त मंत्री, भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
18. वित्त मंत्री, भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरस्थापित करेंगे।
19. पर्यटक मंत्री, उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटक का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
20. पर्यटक मंत्री, उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटक का नियोजित विकास और उन्नयन) विधेयक, 2013 को पुरस्थापित करेंगे।
21. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
22. स्यास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 को पुरस्थापित करेंगे।
23. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
24. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुरस्थापित करेंगे।
25. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

26. श्री जयप्रभात, सदस्य विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

“यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2013 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है”

श्री सुबोध उवियाल, सदस्य विधान सभा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

27. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :
दिनांक : 15 मार्च, 2013

आङ्ग से,
Lachhnaia
(डीएपीओरोला)
प्रमुख सचिव।



प्रथम सत्र, 2013
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 24 फाल्गुन, शक संवत्, 1934
(दिनांक : 15 मार्च, 2012)

नत्थी “क”

तारांकित प्रश्न

श्री बिशन सिंह
चुफाल
14.02.2013

*1. क्या कारागार मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में बन्दी गृहों के कैदी को दो समय कारागार का भोजन के लिए 25 रुपये देय हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मंहगाई को देखते हुए उक्त राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्दन राम
दास
14.02.2013

*2. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में श्रम कानूनों का कड़ाई से श्रम पालन किया जा रहा है तथा प्रदेश में जनपदवार श्रम कानूनों के उल्लंघन के कितने मामले पंजीकृत हैं ? सरकार श्रम कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

श्री मधूख महर
15.02.2013

*3. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका पिथौरागढ़ में मलिन बसितियों में कुल कितने भवन बनाये जा रहे हैं तथा इसमें प्रत्येक मकान तथा कुल मकानों की लागत क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आवंटित धन के सापेक्ष कुल कितना व्यय हो चुका है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के जांघ में भवन निर्माण में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं पायी गयी थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी
विकास

श्री नवप्रभात 15.02.2013	<p>*4. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका विकासनगर के अन्तर्गत 28 फीट रोड पर वर्ष 1989 में 24 दुकानों का निर्माण कर आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो उस समय आवंटित दुकानों का दुकानदारों से कितना प्रीमियम वसूल किया गया था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या वर्ष 2008 में इन आवंटित दुकानदारों से दुकान खाली कराने का अनुबन्ध पालिका द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो क्या खाली करायी गयी दुकानों के स्थान पर नई दुकानों का निर्माण किया गया है ? क्या सरकार द्वारा उन दुकानदारों को जिनसे इस अनुबन्ध के अन्तर्गत दुकानें खाली करायी गयी थी नव निर्मित दुकानों में दुकान आवंटित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?</p>	नगर विकास
श्री चन्दन राम दास 15.02.2013	<p>*5. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर नगर की सीधर लाईन की योजना पूर्व में ४०डी०बी० के फेज-२ में प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो इसे ४०डी०बी० के फेज-३ में डालने का क्या कारण है ? क्या सरकार बागेश्वर में सीधर लाईन की योजना का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?</p>	नगर विकास
श्री पुष्कर सिंह धामी 18.02.2013	<p>*6. चतुर्थ सोम के तारा० ०७ में स्थाना०</p> <p>क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिड्कुल लूद्पुर, खटीमा, हरिद्वार एवं देहसादून स्थापित कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य के बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के प्राविधान का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो ठेकेदारी प्रथा के आधार पर बेरोजगारों को रखे जाने का क्या अधिकार है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक कितने बेरोजगारों को प्राविधानानुसार रोजगार प्रदान किया गया है तथा क्या राज्य सरकार प्रदेश के बेरोजगारों को ठेके प्रथा से निजात दिलाते हुए उक्त प्रतिशतता का अनुपालन सुनिश्चित करवाएगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सिड्कुल लूद्पुर, खटीमा, हरिद्वार एवं देहसादून में स्थापित कम्पनियों द्वारा राज्य के इन्जीनियरिंग एवं व्यावसायिक कालेजों से बी०टैक० एवं एम०बी०ए० कर चुके बेरोजगारों को रोजगार प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस पहल की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?</p>	श्रम एवं सेवायोजन
श्री ललित फर्स्टाण 22.02.2013	<p>*7. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के विभिन्न शहरों में ४०डी०बी० / जे०एन०एन०य०आर०एम० योजना के अन्तर्गत पानी की लाईन डाली गयी थी ? यदि हां, तो क्या ४०डी०बी० / जे०एन०एन०य०आर०एम० योजना के द्वारा पानी की लाईन डालने का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी किलोमीटर लाईन डाली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पानी की लाईन डालने के कारण टूटी सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?</p>	शहरी विकास

श्री नवप्रभात
19.02.2013

*8. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर निगम देहरादून द्वारा नगर कूड़ा निस्तारण के लिये मुस्कान ज्योति नामक संस्था या किसी अन्य संस्था से कोई विकास अनुबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो अनुबंध का विवरण क्या है ?

श्री मदन कौशिक
19.02.2013

*9. क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में हथकरघा खादी एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों के व्यापक कल्याण हेतु कोई कार्य योजना ग्रामोद्योग बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है तथा कब तक कियान्वित की जायेगा ?

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री दान सिंह
भण्डारी
05.10.2012

1. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल स्थित नगर नौकुचियाताल के कमल तालाब के सौन्दर्योक्तरण हेतु कोई ऐसी नीति बनायी जा रही है जिससे कमल तालाब में उगे कमल के फूल भी बढ़ाये जा सकें तथा मछली को भी कोई नुकसान न हो ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त नीति को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री गणेश जोशी
15.02.2013

शहरी
विकास

1. प्रथम सौमवार के अंत 97 में स्थाना०

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 20 जुलाई, 2012 को राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम के नवनिर्मित मुख्यालय भवन के शुभारम्भ के अवसर पर मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा आई०टी० पार्क के लिए ग्रामीणों की पूर्व में अधिग्रहण से मुक्त भूमि का भू-उपयोग पूर्व की भांति आवासीय कराने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप कार्य शुरू कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी सरदत
करीम अंसारी
18.02.2013

2. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में चारा बैंक पशुपालन योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या हरिद्वार की मंगलौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चारा बैंक स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी सरवत
करीम अंसारी
18.02.2013

3. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुकुकट पालन, बकरी पशुपालन पालन की कितनी योजनायें संचालित हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उन सबका विवरण और संचालित सभी योजनाओं पर कितना अनुदान दिया जा रहा है तथा तत्सम्बंधी विवरण क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह
जीना
18.02.2013

4. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में ठेकेदारी के आधार पर पशुपालन श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों/कर्मचारियों को किन-किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ? क्या मंत्री जी उनका जिलेवार पूर्ण विवरण देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह
जीना
18.02.2013

5. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी नस्ल की गायों को और पशुपालन बैलों को लोगों द्वारा छोड़ दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हे संरक्षण देने हेतु गौशाला की व्यवस्था/निर्माण करेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन्हे संरक्षण देती हैं या पालती हैं तो क्या सरकार उसके लिये घारे की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो किस आधार पर? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वन सिंह
चुफाल
19.02.2013

6. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडीहाट शहरी में शौपिंग काम्पलेक्स का निर्माण कार्य बन्द है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य बन्द होने के विकास क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बन्द कार्य को सरकार पुनः शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश जोशी
20.02.2013

7. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के मसूरी शहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गढ़ीकैण्ट क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने हेतु कैण्ट बोर्ड विकास जे०एन०एन०य०आर०एम० के तहत प्रस्ताव शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जे०एन०एन०य०आर०एम० फेज-2 के अन्तर्गत गढ़ी कैण्ट क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वन सिंह
चुफाल
20.02.2013

8. क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के मडमानले क्षेत्र में पशु पशुपालन सेवा केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशुपालन केन्द्र स्वीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विश्वन सिंह
चुफाल
21.02.2013

9. प्रथम बृद्धवार के अंताऽ 47 में स्थाना०

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक धार्मिक स्थल थल में टैक्सी स्टैंड न होने के कारण यात्रियों को रुकने में परेशानी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार थल में टैक्सी स्टैंड बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी
विकास